

and circumstances attending the accident that occurred in the Chasnala Colliery on 27-12-75 has not drawn any conclusion to this effect.

(c) Does not arise.

S.C. & S.T. Employees in Units under SAIL

4387. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in all the units under SAIL in all different grades and their percentage to the total employees separately;

(b) what is the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the recruitment of the last three years specially during the Emergency; and

(c) what steps the Government propose to take to restore the percentages of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the prescribed level?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK):

(a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में भाषणों की सुविधा हेतु धनराशि का नियतन

4388. श्री सुरेन्द्र विप्रम :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में अपने भाषण हेतु के प्रयोजनार्थ अपेक्षित 6 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था करने का निर्णय इस बीच कर लिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगामी अधिवेशन में विदेश मंत्री द्वारा अपना मुख्य भाषण हिन्दी में देने पर कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि दुभाषियों को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति पहले ही दे दी जाएगी।

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारिक भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकारात्मक निर्णय की अपेक्षा होगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में किसी अतिरिक्त भाषा को वहाँ की अधिकारिक भाषा के रूप में चलाने के लिये मौजूदा अनुमानों के अनुसार पहले तीन वर्षों के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत आएगी। चौथे वर्ष का खर्च लगभग 4.2 करोड़ रुपया होगा जो समिति के कारण हर वर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है।

Bokaro Town Planning

4389. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Ukrid village had been acquired by the Bokaro Steel Limited;

(b) whether the villagers were not given any alternative site where they could shift;

(c) whether according to the revised planning Bokaro Steel Limited would not require that village for township;

(d) whether villages desire to pay back the compensation money to retain their village; and

(e) if so, whether Government propose to release Ukrid village from the Bokaro Town Planning?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK):